

(vii) Decision of Kiln Industry to stop manufacture of bricks

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, दिनांक 16-5-1983 को अखिल भारतीय ईंट निर्माता संघ की दिल्ली में हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि अगले वर्ष ईंट भट्टा न चलाया जाय। उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति लखनऊ ने भी अपनी बैठक में आगामी सीजन में भट्टा न चलाने के निर्णय की पुष्टि कर दी है। इसी प्रकार पीलीभीत आदि जिलों की ईंट निर्माता इकाइयों ने भी अगले सीजन में ईंट उद्योग बन्द करने की घोषणा कर दी है। फलस्वरूप इस देशव्यापी ईंट लघु उद्योग में कार्यरत भूमिहीन पिछड़े वर्ग के पांच लाख में भी अधिक श्रमिकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है तथा उन की रोजी-रोटी पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

ईंट निर्माताओं का यह कहना है कि दो-तीन लाख रुपये की पूंजी से लगे इस सीजनल लघु उद्योग की प्रत्येक इकाई पर प्रावीडेंट फण्ड एक्ट, 1952, औद्योगिक निकाय अधिनियम, 1948, इन्टर स्टेट माइग्रेन्ट वर्कमेन एक्ट, 1919, प्रस्तावित काल बैंक वेज एक्ट, बंधुआ मजदूर अधिनियम, 1979, आदि केन्द्रीय कानून तथा मिनिमम वेजिज एक्ट, बाग संरक्षण विधेयक, बिक्री कर अधिनियम, आदि अनेक राज्य अधिनियम लागू कर दिये गये हैं। इतनी बंदिशों के रहते कानून का उल्लंघन किये बिना इस ईंट उद्योग का चल पाना सम्भव नहीं रह गया है। ईंट भट्टा न चलाने के इस निर्णय से सभी व्यक्तिगत अथवा सरकारी निर्माण कार्य रुक जायेंगे। जिस से सम्पूर्ण देश के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जायगी। साथ ही लाखों मजदूरों की रोजी

मिलनी बन्द हो जायेगी। ईंट निर्माण बन्द कर देने के उनके निर्णय को समाप्त कराने के लिए मैं तुरन्त सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की मांग करता हूँ।

(viii) Financial assistance to Tamil Nadu for implementing drinking water schemes

SHRI K.T. KOSALRAM (Truchendur) : Under Rule 377, I make the following statement :

During her visit to Tamil Nadu for personally assessing the extent of drought, the hon. Prime Minister was appalled to see the suffering of the people in rural areas for drinking water. In spite of the special efforts being made by the government of India to provide for potable water to problem villages which have been identified, the paucity of water in villages which have been afflicted by unprecedented drought in Tamil Nadu has become a poser for the very survival of people. In Tamil Nadu all the available potential for exploiting the ground water has been surveyed. It is understood that the Government of Tamil Nadu has sought financial assistance to the tune of Rs. 40 crores from the Centre for implementing a State-wide scheme to provide drinking water to the rural people. Besides the withering away of agricultural crops and the parched earth, in Tamil Nadu the people and the cattle, which is the source of life for rural people, are withering away. In order to save them, it is requested that the Government of India should release the sum of Rs. 40 crores sought by the State Government of Tamil Nadu for implementing the drinking water schemes.

(ix) Irregularities in admission of students in Educational Institutions

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान देश के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में नवीन सत्र के लिये हो रही प्रवेश संबंधी कठिनाइयों की ओर ले जाना चाहता हूँ।